भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1384

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2025

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1384. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जाति आधारित जनगणना के माध्यम से आंकड़े प्राप्त होने के बाद सरकार का पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा को समाप्त करके उन्हें पर्याप्त आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): जनगणना 2027 करने के लिए सरकार ने 16 जून, 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत यह घोषित किया गया है कि वर्ष 2027 के दौरान भारत की जनसंख्या की जनगणना की जाएगी।

*****